भारत संघ

बनाम

श्री शिव शंकर केसरी

सितंबर 14,2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985: धारा 37 (1) (ख) (ii)-जमानत का अनुदान-इसके लिए विचार न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि अभियुक्त दोषी नहीं है और कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है-लेकिन इस प्रकार के निष्कर्ष का मत देना कि आरोपी दोषी नहीं है।

शब्द और वाक्यांश - शब्द 'उचित'अर्थ है-चर्चा की गई।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रतिवादी के पास भारी मात्रा में खसखस का पुआल पाया गया था। विशेष न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा जमानत के लिए अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि अनन्य कब्जे से नहीं थी बरामदगी अभियुक्त में परिवार के अन्य सदस्य मामले में शामिल थे। इस अदालत में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि एन.

डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जिला न्यायाधीश द्वारा जमानत के लिए अनुरोध को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

विस्तृत रूप से पृष्ठभूमि के तथ्यों से निपटना।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारण: एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाएगी जब तक दोनों शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। वे इस प्रकार हैंः न्यायालय में की संतुष्टि प्रकरण "उचित आधार"है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों का संकेत देता है कि अभियुक्त आरोपित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुये उसके साथ अपराध करने की संभावना नही है।

यदि दोनों शर्ते पूरी नही होती है, तो अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

आदेश

1. अपील स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी को जमानत देने को है, जिस पर मादक द्रव्यों की धारा 8, 15, 27-ए और 29 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में

"अधिनियम") का आरोप है कि उसके पास भारी मात्रा में पोस्ता भूसा पाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला है कि छापेमारी दल ने आरोपी-प्रतिवादी के कब्जे से लगभग 400 किलोग्राम पोस्ता भूसी जब्त की। प्रतिवादी द्वारा की गई जमानत की प्रार्थना को विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), वाराणसी ने खारिज कर दिया। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने इस आधार पर जमानत की प्रार्थना स्वीकार कर ली कि बरामदगी आरोपी प्रतिवादी के विशेष कब्जे से नहीं थी और परिवार के अन्य सदस्य मामले में शामिल हैं। यह नोट किया गया कि प्रतिवादी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। तदनुसार, जमानत देने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। (968-ए, बी)

2.1. "उचित"शब्द का कानून में प्रथम दृष्टया अर्थ है -

उन परिस्थितियों के संबंध में उचित जिनके बारे में कर्ता को उचित रूप से कार्य करने के लिए कहा जाता है, वह जानता है या उसे जानना चाहिए। 'उचित'शब्द की सटीक परिभाषा देना मुश्किल है। स्ट्रौड्स जुडिशियल डिक्शनरी, चौथा संस्करण, पृष्ठ 2258 में कहा गया है कि "उचित"शब्द की सटीक परिभाषा की उम्मीद करना अनुचित होगा। कारण के अनुसार इसके निष्कर्षों में भिन्नता होती है व्यक्ति की विशिष्टता, और वह समय और परिस्थितियाँ जिसमें वह सोचता है। जिस तर्क ने पुराने शैक्षिक तर्क का निर्माण किया, वह अब एक बच्चे के खिलौने की झुनझुनी की तरह लगता

है। अक्सर कहा जाता है कि 'उचित'शब्द को एक विशिष्ट अर्थ देने का प्रयास यह गिनने की कोशिश कर रहा है कि क्या संख्या नहीं है और क्या मापने की कोशिश कर रहा है कि क्या स्थान नहीं है। [पारस 8 और 9] 1968-सी, डी, ई]

दिल्ली नगर निगम बनाम। मेसर्स जगन नाथ अशोक कुमार और अन्य [1987] 4 एस. सी. सी. 497 और गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम। यूनिक इरेक्टर्स (गुजरात) प्रा. लि. लिमिटेड और एन. आर. , [1989] 1 एस. सी. सी. 532, पर भरोसा किया।

2.2. 'उचित'शब्द का अर्थ है 'कारण के अनुसार'।

अंतिम विश्लेषण यह तथ्य का सवाल है कि क्या कोई विशेष कार्य उचित है या नहीं, यह किसी दी गई स्थिति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

[पैरा 10] [968-एफ]

नगर निगम ग्रेटर मुम्बई एवं अन्य बनाम कमला मिल्स लिमिटेड, [2003] 6 एस. सी. सी. 325

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार जमानत देने की प्रार्थना स्वीकार करते समय अधिनियम की धारा 37 के मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह बताया गया कि मकान नंबर के 63/121, गोला दीना नाथ, वाराणसी से प्रतिवादी के कब्जे से भारी मात्रा में पोस्ता भूसी बरामद

की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिला न्यायाधीश द्वारा पृष्ठभूमि तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत की प्रार्थना खारिज कर दी गई थी। जमानत केवल दो शर्तों को पूरा करने पर दी जा सकती है यानी (i) जहां यह मानने के लिए उचित आधार हों कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और (ii) जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने जमानत के लिए प्रार्थना स्वीकार करते समय ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि यह मानने के लिए उचित आधार हों कि अभियुक्त दोषी नहीं था। इसके अलावा, ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन विशेष कब्ज़ा स्थापित करने में विफल रहा है और प्रतिवादी आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं है।

5. अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार है:

"37. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।-- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,--

(ए) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(बी) इस अधिनियम के तहत पांच साल या उससे अधिक की कारावास की सजा वाले अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमा के अतिरिक्त हैं। जमानत दिए जाने पर"

6. जैसा कि प्रावधान में ही प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं। वे हैं; न्यायालय की संतुष्टि यह है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। दोनों शर्तों को पूरा करना होगा.यदि इन

दोनों शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो बार संचालित होता है और आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

7. धारा 37 (1) (बी) (ii) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार"है। प्रथम दृष्टया आधार से अधिक इस अभिव्यक्ति का अर्थ एक ही है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों को दर्शाता है कि अभियुक्त आरोपित अपराध के लिए दोषी नहीं है और यह उचित विश्वास ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की ओर इशारा करता है जो संतुष्टि की रिकॉर्डिंग को उचित ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं कि अभियुक्त अपराध के लिए दोषी नहीं है। अपराध आरोपित.

8. कानून में "उचित"शब्द का अर्थ उन परिस्थितियों के संबंध में उचित का प्रथम दृष्टया अर्थ है जिनके बारे में अभिनेता, जिसे उचित रूप से कार्य करने के लिए कहा जाता है, जानता है या जानना चाहिए। "उचित"शब्द की सटीक परिभाषा देना कठिन है।

> "7.... स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ 2258 में कहा गया है कि 'उचित'शब्द की सटीक परिभाषा की अपेक्षा करना अनुचित होगा। व्यक्ति की विशिष्टताओं के अनुसार तर्क अपने निष्कर्षों में भिन्न होता है, और वह समय और परिस्थितियाँ जिसमें वह सोचता है। जिस तर्क ने

पुराने शैक्षिक तर्क का निर्माण किया वह अब एक बच्चे के खिलौने की झंकार जैसा लगता है।"

{(देखें दिल्ली नगर निगम बनाम लगन नाथ अशोक कुमार [(1987) 4 एससीसी 497] और गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम यूनिक इरेक्टर्स (गुजरात) (पी) लिमिटेड [(1989) 1 एससीसी 532]}.

9. अक्सर यह कहा जाता है कि 'उचित' शब्द को एक विशिष्ट अर्थ देने का प्रयास यह है कि जो संख्या नहीं है उसे गिनें और जो स्थान नहीं है उसे मापें। शब्द और वाक्यांश के लेखक (स्थायी संस्करण) ने उक्त शब्द के लिए एक प्रशंसनीय अर्थ देने के लिए नाइस एंड श्रेइबर, इन री [123 एफ 987 एट पी. 988] से उद्धृत किया है। वह कहते हैं: 'उचित' अभिव्यक्ति एक सापेक्ष शब्द है, और जो उचित है उसे निर्धारित करने से पहले विशेष विवाद के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। इसका मतलब समीचीन या सुविधाजनक होना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इससे कुछ अधिक है।

10. "उचित"शब्द का अर्थ "तर्क के अनुरूप"है। अंतिम विश्लेषण में यह तथ्य का प्रश्न है कि कोई विशेष कार्य उचित है या नहीं, यह किसी दी गई स्थिति में परिस्थितियों पर निर्भर करता है।(ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम कमला मिल्स लिमिटेड देखें। [(2003) 6 एससीसी 315]।

11. अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को दोषी नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नहीं कहा जाता है। यह सीमित उद्देश्य के लिए है जो अनिवार्य रूप से आरोपी को जमानत पर रिहा करने के सवाल तक ही सीमित है, अदालत को यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और ऐसे आधारों के अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करता है। लेकिन न्यायालय को इस मामले पर इस तरह विचार नहीं करना चाहिए जैसे कि वह बरी करने का फैसला सुना रहा हो और दोषी न होने का निष्कर्ष दर्ज कर रहा हो।

12. इसके अतिरिक्त, न्यायालय को यह निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि जमानत पर रहने के दौरान आरोपी द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ सामग्री भी मौजूद होनी चाहिए।

13. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था। प्रतिवादी ने यह रुख अपनाया है कि यह जबरदस्ती के तहत किया गया था। ऐसे रुख की स्वीकार्यता परीक्षण का विषय है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने इस बारे में कोई कारण नहीं बताया है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि प्रतिबंधित सामग्री आरोपी-प्रतिवादी के विशेष कब्जे से जब्त नहीं की गई थी।

14. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, विवादित आदेश स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। अधिनियम की धारा 37 के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। आरोपी के हिरासत में आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत अर्जी पर विचार किया जाएगा। आरोपी-प्रतिवादी को तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। उच्च न्यायालय के लिए अच्छा होगा कि आरोपी के हिरासत में आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत अर्जी का शीघ्रता से निपटारा किया जाए।

15. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी साक्षी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।